



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, ४ दिसम्बर, 2023

अग्रहायण १३, १९४५ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग—२

संख्या-एस-२-१/४३८८७१ / दस-२०२३-१८६२-२०२१

लखनऊ, ४ दिसम्बर, २०२३

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०—४९

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

1—(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, संक्षिप्त नाम 2023 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(दो) यह 01 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992, में नीचे स्तम्भ—१ में दिये गये नियम 17 का विद्यमान नियम—१७ के स्थान पर स्तम्भ—२ में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः— प्रतिस्थापन

स्तम्भ—१

वर्तमान नियम

17—ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी—दो :— ज्येष्ठ

वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को वेतनमान श्रेणी दो में चयन, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी चयन समिति की संस्तुति पर साधारण श्रेणी

स्तम्भ—२

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

17—ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी—दो :— ज्येष्ठ

स्तम्भ-1**वर्तमान नियम**

के ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होंने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमें चयन किया जाय, उस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जाएगी :-

(i) सरकार के वित्त विभाग के यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव अध्यक्ष

(ii) सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव प्रमुख सचिव/सचिव – या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी (दो) कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न के यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख हो— सदस्य सचिव/सचिव या उसके नाम निर्देशिती

(iii) कोषागार निदेशक, उ० प्र०सदस्य जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो— सदस्य

(तीन) निदेशक, कोषागार

उत्तर प्रदेश— सदस्य

आज्ञा से,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी-दो में चयन के लिए नियत सेवा सीमा को शिथिल कर सकती है।